

## बुलडोज़र न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दशान-नरिदेश

### प्रलिमिंस के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142, नगरपालिका कानून, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वधिका शासन, सम्मान से जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 51, जनिवा कन्वेंशन 1949, वधिद्वारा स्थापित प्रक्रिया, वधिकी समयक प्रक्रिया, मेनका गांधी मामला 1978, हेट स्पीच, न्यायाधिकरण, वैकल्पिक विवाद समाधान।

### मेन्स के लिये:

संपत्तियों को ध्वस्त करने हेतु उचित प्रक्रिया का पालन।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने संविधान के [अनुच्छेद 142](#) के तहत अखिल भारतीय दशान-नरिदेश दिये हैं ताकियह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों की संपत्तियों को ध्वस्त करने हेतु उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना किसी आरोपी या दोषी की संपत्ति को ध्वस्त करना "असंवैधानिक" है।
- संबंधित मामले में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को "अवैधानिक" तरीके से ध्वस्त करने को चुनौती दी गई थी, जैसा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में देखा गया है।

**नोट:** बुलडोज़र न्याय से तात्पर्य उन संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रथा (कभी-कभी उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किये बिना) से है जो अक्सर अपराध के आरोपी लोगों की होती हैं।

## बुलडोज़र न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के दशानरिदेश क्या हैं?

- **नोटिस देना:** किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से पहले संपत्ति के मालिक को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिये।
  - नोटिस में ध्वस्त किये जाने वाले ढाँचे का विवरण तथा ध्वस्त किये जाने के कारण स्पष्ट रूप से उल्लिखित होने चाहिये।
- **नधिपक्ष सुनवाई:** व्यक्तितगत सुनवाई के लिये नरिधारित समय देना चाहिये, जिससे प्रभावित पक्ष को वधिवंस का वरिोध करने या स्थितिको स्पष्ट करने का अवसर मिल सके।
- **पारदर्शिता:** प्राधिकारियों को नोटिस भेजने के बाद स्थानीय कलेक्टर या ज़िला मजिस्ट्रेट को ई-मेल के माध्यम से सूचित करना होगा।
- **अंतिम आदेश जारी करना:** अंतिम आदेश में संपत्ति मालिक के तर्क, ध्वस्तीकरण को एकमात्र विकल्प मानने का प्राधिकारी का औचित्य तथा यह कि क्या संपूर्ण संरचना या आंशिक संरचना को ध्वस्त किया जाना है, शामिल होना चाहिये।
- **अंतिम आदेश के बाद की अवधि:** यदि ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया जाता है, तो इसके क्रियान्वयन से पहले 15 दिन का समय दिया जाए, जिससे संपत्ति मालिक को संरचना को हटाने या आदेश को न्यायालय में चुनौती देने का मौका मिल सके।
- **वधिवंस का दस्तावेज़ीकरण:** प्राधिकरण को वधिवंस का वीडियो रिकॉर्ड करना होगा और पहले से ही एक "नरिीक्षण रिपोर्ट" तैयार करनी होगी, साथ ही इसमें शामिल कर्मियों की सूची वाली एक "वधिवंस रिपोर्ट" भी तैयार करनी होगी।
- **दोहरे उल्लंघन के लिये परीक्षण:** सर्वोच्च न्यायालय ने उन मामलों के लिये एक अलग परीक्षण नरिधारित किया है, जहाँ ध्वस्त की गई संपत्ति में किसी आरोपी का नविस हो और अवैध नरिमाण के रूप में उस संपत्ति द्वारा नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन होता हो।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि केवल एक संरचना को ध्वस्त किया जाता है, जबकि समान संरचनाओं को अछूता छोड़ दिया जाता है, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि इसका उद्देश्य आरोपी को दंडित करना है, न कि अवैध नरिमाण को हटाना।

- **अपवाद:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहाँ सड़क, गली या फुटपाथ जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पर, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय के समीप कोई अनधिकृत संरचना है तथा उन मामलों में भी लागू नहीं होंगे, जहाँ न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है।

## अनुच्छेद 142

- संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय के लिये आवश्यक आदेश और डिक्री पारित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को सम्पूर्ण न्याय करने के लिये पूरे भारत में प्रवर्तनीय आदेश पारित (राष्ट्रपतिद्वारा नरिधारित) करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 142(2) न्यायालय को उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेजों की खोज करने या अवमानना के लिये दंड देने की शक्ति प्रदान करता है।
- समय के साथ, इस प्रावधान का उपयोग "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने और वधायी खामियों को दूर करने के लिये किया गया है।

## सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेशों का क्या महत्त्व है?

- **शक्तियों का पृथक्करण:** फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि न्यायापालिका के पास दोष तय करने तथा यह नरिधारित करने की शक्ति है कि क्या राज्य के किसी अंग ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया है।
  - कार्यपालिका अपने मूल कार्यों के निष्पादन में न्यायापालिका का स्थान नहीं ले सकती।
- **वधिका शासन:** न्यायालय ने कहा कि बिना उचित सुनवाई के किसी को दण्ड के रूप में ध्वस्त करना कार्यपालिका के लिये अनुचित है। यह सुनिश्चित करके वधिका शासन को कायम रखता है कि राज्य की कार्रवाई संविधानिक सीमाओं का उल्लंघन न करे।
  - ऐसे वधिवंस जो कुछ समुदायों (जैसे झुग्गीवासियों) को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, उन्हें अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण के रूप में चुनौती दी जा सकती है।
- **अधिकारियों की जवाबदेही:** यह अनविरय करके कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की सार्वजनिक रूप से जाँच की जाए तथा वसित्त रिकॉर्ड (जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग और नरिरीक्षण रिपोर्ट) प्रस्तुत किए जाएँ, दशा-नरिदेशों का उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना तथा अधिक जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
- **आवास का अधिकार:** सम्पूर्ण संपत्त को प्रभावित करने वाला वधिवंस, जिसमें आरोपी न होने वाले लोग भी शामिल हैं, असंविधानिक होगा क्योंकि यह आवास के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार में आश्रय या आवास का अधिकार भी शामिल है।
  - अनुच्छेद 300A गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अलावा उसकी संपत्त से वंचित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान इस बात पर जोर देता है कि संपत्त को केवल उचित प्रक्रिया एवं वैध कानूनों के तहत ही छीना जा सकता है।
- **व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण:** उचित प्रक्रिया और शक्तियों के पृथक्करण पर न्यायालय व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से बचाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन की आड में अधिकारों का उल्लंघन न हो।
- **जनिवा कन्वेंशन, 1949:** जनिवा कन्वेंशन 1949 का अनुच्छेद 87(3) सामूहिक दंड पर प्रतिबंध लगाता है।
  - इस तरह के वधिवंस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का भी उल्लंघन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय संधियों और कानूनों का सम्मान करना चाहिये।

## बुलडोजर न्याय एक चिता का वषिय क्यों है?

- **दंडात्मक वधिवंस में वृद्धि:** आवास और भूमि अधिकार नेटवर्क (HLRN) के वर्ष 2024 के अनुमान में पाया गया कि अधिकारियों ने वर्ष 2022 और 2023 में 153,820 घरों को ध्वस्त कर दिया, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 738,438 से अधिक लोग वसिथापति हो गए।
- **नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR):** ICCPR के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ मलिकर संपत्त रखने का अधिकार है, और किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्त से वंचित नहीं किया जाएगा।
- **सामूहिक दंड:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ध्वस्तीकरण अभियान न केवल अपराध के कथित अपराधियों को नशाना बनाता है, बल्कि उनके नविस स्थान को नष्ट करके उनके परिवारों पर एक प्रकार का "सामूहिक दंड" भी लगाता है।
- **त्वरति न्याय:** अतिक्रमण या अनधिकृत नरिमाण के खिलाफ कार्रवाई के रूप में तोड़फोड़ को उचित ठहराया गया है। दंडात्मक हिसा के ऐसे राज्य-सवीकृत कृत्यों को "त्वरति न्याय" के रूप में सराहा गया है।

## संपत्त वधिवंस से संबंधित अन्य न्यायिक घोषणाएँ

- **मेनका गांधी केस, 1978:** सर्वोच्च न्यायालय ने "कानून द्वारा सथापित प्रक्रिया" के दायरे का वसितार करते हुए नरिणय दिया कि यह न्यायसंगत, निषिक्ष और उचित होनी चाहिये, जिससे "कानून की उचित प्रक्रिया" के सिद्धांत का प्रवर्तन हुआ।

- इसलिये संदेह या नरिधार आरोपों के आधार पर की गई तोड़फोड़ न्याय, नषिपक्षता और गैर-मनमानी के सदिधांतों के वपिरीत है।
- ओलगा टेलसि केस, 1985: सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टिकी कजिजीवन के अधिकार की गारंटी देने वाले अनुच्छेद 21 में आजीविका और आशर्य का अधिकार भी शामिल है।
  - इसका अरथ है कबिना उचति प्रकरया के घरों को धवसत करना संवैधानकि अधिकारों का उल्लंघन है।
- के.टी. प्लांटेशन (P) लमिटिड केस, 2011: सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला दया क अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्तिसे वंचति करने का प्रावधान करने वाला कानून न्यायसंगत, नषिपक्ष और उचति होना चाहयि।

## सर्वोच्च न्यायालय दशा-नरिदेशों के कार्यानवयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- राजनीतकि इच्छाशक्तपर नरिभरता: प्रतशिोध या नवारण के रूप में वधिंवस का उपयोग करने का राजनीतकि दबाव, वशिष रूप से राजनीतकि रूप से आवेशति वातावरण में, बना रह सकता है।
- दंड से मुक्तकी संसकृत: हालाँकि दशा-नरिदेश अधिकारियों पर जवाबदेही थोपते हैं, लेकनि ऐतहिासकि उदाहरण, जैसे क हिेट सपीच या मॉब लचिगि जैसे मुद्दों को संबोधति करने के लयि न्यायालय के पछिले प्रयास, यह सुझाव देते हैं क इसी तरह के प्रयासों से हमेशा परयाप्त परणाम या जवाबदेही नहीं मली है।
- नगरानी का अभाव: यह जोखमि बना रहता है क स्थानीय प्राधिकारी या अधिकारी इन नयिमों को दरकनार करने के तरीके ढूँढ लेंगे, वशिष रूप से उन कषेत्रों में जहाँ न्यायकि नगरानी कमज़ोर है।
- दीर्घकालकि सांसकृतकि परविरतन: अकेले दशा-नरिदेश व्यापक सांसकृतकि और संस्थागत प्रथाओं को बदलने के लयि परयाप्त नहीं हो सकते हैं जो इस तरह की काररवाइयों की अनुमति देते हैं।

## आगे की राह

- कानून के शासन को कायम रखना: सभी राज्ज काररवाई कानून के सखत अनुपालन में होनी चाहयि। कानूनी प्रणाली को आपराधकि न्याय और सामूहकि दंड के बीच अंतर करना चाहयि, यह सुनशिचति करते हुए क निरिदोषता की धारणा कायम रहे।
- न्यायकि नगरानी को बढ़ाना: संपत्तकि वधिंवस से संबंधति वविादों से वशिष रूप से नपिटने के लयि वशिष न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी चाहयि, जनिके पास सरकारी नरिणयों की समीकषा करने की शक्तियाँ हों।
- वैकल्पकि वविाद समाधान: संपत्ति अधिकारों और वधिंवस से संबंधति वविादों को हल करने के प्रभावी तरीके के रूप में मध्यस्थता और पंचनरिणय जैसे तंत्रों को सकरयि रूप से बढ़ावा दया जाना चाहयि।
- पुनरवास योजनाएँ: वधिंवस से प्रभावति व्यक्तियों के लयि वसितृत पुनरवास योजनाएँ बनाना महत्त्वपूर्ण है, जसिमें वैकल्पकि आवास, आजीविका सहायता और मानसकि स्वास्थय सेवाओं तक पहुँच का प्रावधान हो।

?????? ???? ?????:

प्रश्न: 'बुलडोजर न्याय' के संदर्भ में संपत्ति वधिंवस पर सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेश कसि प्रकार उचति प्रकरया, पारदर्शति और जवाबदेही के सदिधांतों को सुदृढ करते हैं?